



स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड ट्रंप ने दुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव...>Pg12

केडीए एक्सईएन ने वीसी को किया गुमराह!>Pg03 मूल्य: 2 ₹

कानपुर-बुंदेलखंड में 'ठाकुर प्रतिनिधित्व' बना सियासी मुद्दा

2027 से पहले भाजपा के सामने संतुलन की चुनौती



स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कानपुर-बुंदेलखंड की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर 'ठाकुर प्रतिनिधित्व' को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चंदेल, कछवाह, परमार और चौहान वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले इस क्षेत्र में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में क्षत्रिय समाज को प्रतिनिधित्व न मिलने को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार मंथन चल रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर संगठन और सामाजिक मंचों तक यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र से ठाकुर बिरादरी को सरकार में स्थान क्यों नहीं मिला।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में क्षत्रिय समाज का प्रभाव कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक माना जाता है। इसके बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्र से किसी भी ठाकुर चेहरे को जगह न मिलना स्थानीय राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। खास बात यह है कि क्षेत्र में ठाकुर बिरादरी के 3 विधायक और 4 विधान परिषद सदस्य मौजूद हैं, जिससे समर्थकों की अपेक्षाएं और अधिक बढ़ गई थीं।

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की 52 सीटों में से 6 सीटों पर ठाकुर नेताओं को प्रत्याशी बनाया था, जिनमें से 3 नेता जीतकर विधानसभा पहुंचे। चुनाव परिणामों के बाद यह माना जा रहा था कि सरकार क्षेत्रीय और जातीय संतुलन

→ कानपुर-बुंदेलखंड में क्षत्रिय चेहरे की तलाश तेज, संगठन में भरपाई की चर्चा

2022 के आंकड़ों ने बढ़ाई थी उम्मीदें



साधने के लिए किसी एक क्षत्रिय चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने पर अब राजनीतिक असंतोष की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी हैं।

हालांकि भाजपा के भीतर इसे खुलकर विरोध के रूप में नहीं देखा जा रहा, लेकिन समर्थकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा जरूर है कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग और ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिलने के

2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखी जा रही रणनीति

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों पर बेहद सावधानी से काम कर रही है। पार्टी की कोशिश गैर-यादव पिछड़ा, दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने की है, लेकिन साथ ही क्षत्रिय समाज की नाराजगी को भी लंबे समय तक नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सूत्रों की मानें तो अब पार्टी संगठन विस्तार में कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी प्रभावशाली ठाकुर चेहरे को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर संतुलन साधने की तैयारी कर सकती है। संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी या बोर्ड-निगमों में नियुक्तियों के जरिए संदेश देने की रणनीति पर भी चर्चा बताई जा रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। 2027 के चुनाव में जातीय समीकरण एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में भाजपा किसी भी प्रभावशाली सामाजिक वर्ग को असंतुष्ट छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। प्रदेश की राजनीति में यह संदेश तेजी से फैल रहा है कि सत्ता में भागीदारी और संगठन में सम्मान अब आने वाले चुनावी समीकरणों का बड़ा आधार बनने जा रहा है। यही वजह है कि कानपुर-बुंदेलखंड में ठाकुर प्रतिनिधित्व का मुद्दा धीरे-धीरे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है।

बाद ठाकुर समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है।

योगी मंत्रिमंडल में नई एंट्री, पश्चिम से पूर्वांचल तक भाजपा का संतुलन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को छह नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जबकि दो मंत्रियों को प्रमोशन देकर बड़ा संदेश दिया गया। नए चेहरों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडेय, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत शामिल हैं। वहीं सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को प्रमोशन का तोहफा मिला।

भाजपा ने इस विस्तार के जरिए जाट, ब्राह्मण, पासी, वाल्मीकि, लोध, गुर्जर और पाल समाज को साधने का बड़ा सियासी दांव चला है। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा ने संगठन और सामाजिक समीकरण दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाकर पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक को साधने का प्रयास किया गया है, जबकि सपा छोड़कर भाजपा के करीब आए मनोज पांडेय को कैबिनेट में जगह देकर ब्राह्मण राजनीति को नया संदेश दिया गया है। कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर के जरिए दलित और वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं वाराणसी में संगठन मजबूत करने वाले हंसराज विश्वकर्मा को शामिल कर भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ा सियासी संदेश भी दिया है। मेरठ के सोमेंद्र तोमर और कानपुर देहात के अजीत सिंह पाल को प्रमोशन देकर पश्चिम यूपी और अति पिछड़े वोट बैंक पर पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति साफ कर दी है।

- जातीय समीकरण से लेकर संगठन साधने तक, विस्तार में दिखा भाजपा का चुनावी गणित
- सपा-कांग्रेस की घेराबंदी के साथ पश्चिम और पूर्वांचल पर फोकस

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे पर नजर

लखनऊ। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेंद्र सिंह चौधरी और वरिष्ठ नेता मनोज कुमार पांडेय को सरकार में महत्वपूर्ण विभाग मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दोनों नेताओं को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी के साथ बड़े मंत्रालय सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राज्यमंत्री से प्रमोट होकर कैबिनेट में पहुंचे डा. सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल को भी अहम जिम्मेदारियां दिए जाने की चर्चा है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि डा. सोमेंद्र तोमर को ऊर्जा विभाग में अनुभव का लाभ मिल सकता है। वह अभी तक ऊर्जा राज्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, ऐसे में उन्हें ऊर्जा विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिए जाने की अटकलें तेज हैं। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में ऊर्जा और नगर विकास जैसे दो बड़े विभाग मंत्री ए.के. शर्मा के पास हैं। ऐसे में सरकार इन विभागों में संतुलन बनाते हुए कुछ जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण कर सकती है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को भी किसी कद्दावर मंत्री को सौंपे जाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ कई पुराने मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है।

केडीए के बगल में अधिवक्ताओं की आड़ में दलालों का कब्जा

» केडीए दीवार से सटे बने कई टीनशेड और दुकानें सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

» आईजीआरएस में हुई शिकायत को नगर निगम अधिकारियों ने दबाया

» केडीए और नगर निगम के कूटरचित दस्तावेज बना रहे दलाल



प्रकरण की जानकारी जोनल अधिकारी से मांगी गई है। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शहर में अतिक्रमण को लेकर कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रआई के माध्यम से जांच की जा रही है।

अर्पित उपाध्याय, नगर आयुक्त

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर कई साल पहले केडीए के बगल में नगर निगम से मामूली यूजरचार्ज पर करीब 30 दुकानें चिन्हित हुई थी लेकिन वर्तमान समय में 50 से अधिक दुकानें खुल गई हैं। इनमें अधिकतर दलालों के अड्डे बन गए हैं, जहां से कूटरचित दस्तावेज सहित अन्य आपराधिक कृत्य किए जा रहे हैं। मामले में जनसुनवाई पोर्टल पर एक जागरूक युवक ने शिकायत भी की लेकिन नगर निगम जोन-4 के अधिकारियों ने मामले को दबा दिया।

नगर निगम जहां पूरे शहर में अतिक्रमण खाली करवाता है वहीं, अपने आंगन में झांकने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। हालात यह हैं कि नगर निगम मुख्यालय



के पास केडीए के बगल में नगर निगम प्रेस के पास फुथपाथ घेरकर तमाम दुकानें बना दी गई हैं। यहां पर अधिवक्ताओं की आड़ में दलालों का गैंग बैठा है। यह गैंग केडीए में घुसपैठ करके फाइलों में हेराफेरी को अंजाम देता है। यहां पर कुछ ऐसे दलाल हैं जो कि जन्म मृत्यु के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नगर निगम को धोखा देते हैं। इस तरह से यहां पर दलालों की अराजकता के चलते आमजन के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। गोविंदनगर कानपुर निवासी निखिल ठाकुर ने 27 फरवरी 2026 को सीएम पोर्टल में जनसुनवाई संख्या 60000260049853 दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यहां पर कई फर्जी अधिवक्ता और दलालों का कब्जा है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम 2 हजार से लेकर 5 हजार तक रूप्य वसूल जा रहे हैं। इसके अलावा टाइपिंग, फोटोकॉपी के नाम पर मनमाने पैसे मांगे जाते हैं। शिकायत करने के बाद भी



जोन-4 के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक शिकायतकर्ता का नंबर पब्लिक को दे दिया गया जिससे लोग फोन करके शिकायत न करने की धमकी देते हैं। पीडित ने कहा कि यदि मामले कार्रवाई न हुई तो मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की जाएगी। वहीं, जोनल अधिकारी राजेश सिंह का कहना है कि आरास्ते में खड़े होते वाहन, निकलना मुश्किल

केडीए के बगल में डामरवाली चौड़ी सड़क बनी हुई है। वहीं से नगर निगम उद्यान, ट्रैफिकसेल, नगर निगम प्रेस सहित अन्य कार्यालयों को जाने का रास्ता है। स्थिति यह रहती है कि सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने भी अवैध दुकानें एवं अतिक्रमण हटाने की मांग की है।

सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम ने लौटाए 101 खोए मोबाइल

करीब 22 लाख रुपये कीमत के मोबाइल पाकर खिले लोगों के चेहरे



स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर कमिश्नरेट पुलिस की सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम ने सहायनीय कार्य करते हुए नागरिकों के खोए हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए। रिकवर किए गए मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 22 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जांच के जरिए विभिन्न स्थानों से मोबाइल फोन खोजकर उनके वास्तविक स्वामियों तक पहुंचाए गए। पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव और अपर पुलिस उपायुक्त डॉ. अर्चना सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोबाइल फोन संबंधित लोगों को सुपुर्द किए। लंबे समय बाद अपने खोए हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी।

फर्जी पुलिस बनकर करते थे लूट, दो अंतर्राज्यीय बदमाश गिरफ्तार

कलेक्टरगंज पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई, नकदी और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस ने चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना कलेक्टरगंज पुलिस और सर्विलांस सेल पूर्वी जोन की संयुक्त टीम ने आरोपियों को कोपरगंज रोड स्थित मंदिर के पास से दबोचा। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के 30,150 रुपये और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के मुताबिक, 1 मई 2026 को कलेक्टरगंज थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर भी



नजर रखी जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि वारदात में शामिल आरोपी किसी नई घटना को अंजाम देने की तैयारी में मंदिर के पास मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में

आरोपियों ने कई चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कंजर उर्फ भोगी उर्फ रिशु उर्फ रोहन तथा जीतू उर्फ साधू के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पुलिस की वर्दी और टोपी



आरोपी पुलिस की वर्दी में

पहनकर लोगों को झांसे में लेते थे। वे राहगीरों को लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठकर सुनसान इलाके में ले जाते और फिर तमंचा दिखाकर लूटपाट करते थे। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया। पुलिस अब उनके आपराधिक इतिहास और अन्य वारदातों में संलिप्तता की जांच कर रही

KDA एक्सईएन नरेंद्र ने वीसी को किया गुमराह!

केडीए अधिकारियों की आंखों पर बंधी 'पट्टी' या मिलीभगत ?

स्वराज इंडिया फालोअप

→ अनाथ बेटी के आशियाने को हथियाने में जुटे इन्सानी रुपी 'भेड़िये'!



क्या बचेगा ओश का आशियाना ?

बीबीए की छात्रा ओश सिंह आज किताबों के साथ-साथ कचहरी और दफतरो के चक्कर काट रही है। कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर उसने केडीए के उच्चाधिकारियों से न्याय की भीख नहीं, बल्कि अपने अधिकार की मांग की है। क्योंकि कालोनी से सम्बन्धित, मूल आवंटनी की पुत्री द्वारा किया गया नोटरी इकरारनामा, मूल आवंटनपत्र व अन्य रसीदें ओश के पास वर्ष 2008 से हैं और उन्हीं के आधार पर उसके माता-पिता काबिज रहे और उनके देहावसान के बाद से स्वयं उसी का कब्जा है।

हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि, 'क्या एक जिम्मेदार अधिकारी का दायित्व पीड़ित को न्याय दिलाना है या 'कुछ' के लालच में, शातिरों के हाथों की कठपुतली बनकर एक अनाथ बेटी का

शातिरों की कुदृष्टि और ऋष्ट तंत्र का है अटूट गठजोड़ !

उपरोक्त यह कोई पहली घटना नहीं है। कानपुर का बर्रा क्षेत्र ऐसे दर्जनों विवादों का गवाह रहा है, जहाँ रसूखदारों ने मध्यमवर्गीय और असहाय लोगों की सम्पत्तियों को केडीए के कुदिल अधिकारियों की मिलीभगत से हथिया लिया है। ऐसे में सवाल गम्भीर है कि, 'क्या प्रशासन सो रहा है? या फिर इन शातिरों को सत्ता और सिस्टम का मूक समर्थन प्राप्त है? वहीं जबतक प्राधिकरण अपनी नीति व सौच में बदलाव नहीं करेगा तो भविष्य में ऐसे ही नजारे रहेंगे ! "स्वराज इण्डिया" को मिली जानकारी के अनुसार, ओश सिंह के पास ही नहीं अपितु शहर के दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे अनेक वासिन्दे हैं, जिन्होंने नोटरी अथवा पावर ऑफ अटॉर्नी के बलबूते मकान खरीद रखे हैं। कुछ के पास दस्तावेज पंजीकृत हैं तो कुछ के पास अपंजीकृत, जबकि प्राधिकरण अथवा परिषद् के अधिकारी इन दस्तावेजों को निराधार मानकर मूल आवंटनी को ही वरीयता देते हैं, जोकि वाद-विवाद का कारण बन रहा है और मूल आवंटनी को अपनी नियत खराब करने हेतु उकसाने का काम कर रही है।

साजिश का ताना-बाना और शातिरों की 'गिद्ध दृष्टि'

मामले की जड़ें साल 2008 के उस इकरारनामे में हैं, भले ही वह पंजीकृत हो या न हो, जिसके तहत ओश के पिता उमेश सिंह ने बर्रा-8 स्थित भवन संख्या सी./148 में रहने का अधिकार प्राप्त किया था। सभी मूल दस्तावेज, रसीदें और वर्षों का कब्जा चीख-चीख कर सच बयां कर रहे हैं। बिजली का कनेक्शन, सालों की रिहाइश और आसपड़ोस के लोग, यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि यह घर ओश का है। लेकिन, जैसे ही माता-पिता का साया ओश के सिर से उठा, मूल आवंटनी के तथाकथित 'शातिर' उत्तराधिकारी गिद्धों की तरह सक्रिय हो गए। कूटरचित दस्तावेजों और झूठे दावों के दम पर, केडीए के कुछ ऋष्ट चेहरों के साथ साँटगाँठ कर, इस छात्रा को बेधर करने की नोटिस रुपी तलवार लटका दी गई है।

पुलिस अधिकारियों से न्याय का साथ देने की गुहार

पीड़िता कु. ओश सिंह ने पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेन्द्र चौधरी के समक्ष पेश होकर सभी तथ्यों से अवगत कराकर उनको एक प्रार्थना पत्र देकर अपने हक व अधिकारों की रक्षा करने की गुहार लगाई है। उसने माँग करी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर उसके साथ न्यायपरक कार्रवाई की जाये। न्यायप्रिय समाज की नजरें अब केडीए की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह केवल एक मकान का नहीं, बल्कि विश्वास और न्याय की हत्या का मामला है।



प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर . शहर के बर्रा इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जहाँ कानून के रखवाले और समाज के रसूखदार मिलकर एक बेसहारा छात्रा के भविष्य को अंधकार में धकेलने की बिसात बिछा रहे हैं।

विश्व बैंक पोषित परियोजना के तहत बर्रा-8 में आवंटित भवन संख्या सी./148 आज उस भ्रष्टाचार और साजिश का केंद्र बन गया है, जहाँ एक अनाथ बेटी, ओश सिंह, अपने आशियाने को बचाने की लड़ाई लड़ रही है।

इस पूरे प्रकरण में कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अभियन्त्रण अनुभाग, जोन-3 के अधिशाषी अभियन्ता (एक्सियन) नरेन्द्र की भूमिका अत्यन्त संदेहास्पद और किसी 'खलनायक' से कम नहीं प्रतीत हो रही है। आरोप है कि सबकुछ जानते हुए यह अधिकारी अज्ञान बनकर सही तथ्यों को केडीए उपाध्यक्ष से छिपाकर न केवल उन्हें गुमराह कर रहा है, बल्कि न्याय का गला घोटने पर आमादा हैं। हो सकता है कि इसके पीछे 'कुछ' का खेल

केडीए का बुलडोजर फिर गरजा, 8.5 बीघे में अवैध निर्माण और प्लाटिंग ध्वस्त

विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही की गई

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनाधिकृत प्लाटिंग के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को प्रवर्तन जोन-1बी क्षेत्र में लगभग 8.5 बीघे में विकसित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष अंकुर कौषिक और सचिव अभय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई।

प्राधिकरण की टीम ने बैरी अकबरपुर बांगर क्षेत्र में श्री हरि मोहन गुप्ता व अन्य द्वारा लगभग 3 बीघे क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे अवैध गेस्ट हाउस और होटल निर्माण को ध्वस्त किया। केडीए अधिकारियों के अनुसार

निर्माणकर्ता द्वारा बिना प्राधिकरण से अनुमति लिए व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था, जिसके खिलाफ नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अलावा कटरी क्षेत्र में श्री रामबाबू, मोनू यादव व अन्य द्वारा लगभग 5.5 बीघे में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर भी केडीए का बुलडोजर चला। प्राधिकरण का कहना है कि बिना ले-आउट स्वीकृति और अनुज्ञा के विकसित की जा रही इस प्लाटिंग को ध्वस्त कर अवैध कब्जों और भू-माफियाओं पर सख्त संदेश दिया गया है।

कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता हिमांशु बर्नवाल, सुपरवाइजर रामऔतार, मनोज कुमार, राजकुमार और लाल सिंह सहित संबंधित थाने का भारी पुलिस बल मौजूद रहा। डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया

कि लगभग 9.5 बीघे में और अवैध प्लाटिंग चिन्हित की गई है, जिसके विरुद्ध 15 मई को ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी प्लाट या भूमि की खरीद से पहले केडीए से ले-आउट और मानचित्र स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा जा सके। केडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण सीमा में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण, होटल, गेस्ट हाउस या प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।



मंजुल आईटीआई में वृहद रोजगार मेले का आयोजन

250 युवाओं को मिला रोजगार



» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मेहरबान सिंह का पुरवा स्थित मंजुल आईटीआई में शुरुवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन

किया गया, जिसमें देश की 12 प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रतिभाग कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। रोजगार मेले में टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, मारुति

सुजुकी, एयरटेल, भारत वायर्स समेत कई नामी कंपनियों ने प्रतिभाग किया।

रोजगार मेले में कानपुर नगर व आसपास के क्षेत्रों से लगभग 400 से 500 छात्रों ने हिस्सा लिया। विभिन्न कंपनियों द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षण के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मेले में लगभग 250 छात्रों का विभिन्न प्रतिष्ठानों में चयन होने पर चयनित युवाओं एवं उनके परिजनों में खुशी का माहौल रहा। संस्था के प्रधानाचार्य एस.एन.



दुबे ने कहा कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध कराना संस्था की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे रोजगार मेलों से छात्रों को सीधे उद्योगों से जुड़ने का अवसर मिलता है तथा उनके भविष्य को नई दिशा मिलती है। इस अवसर पर प्लेसमेंट ऑफिसर आशुतोष दुबे, शिवानी साहू, मयंक दुबे, काजल यादव, शैलेंद्र सिंह, अंकित शर्मा सहित संस्था के शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सीटीईटी नोटिफिकेशन जारी, आवेदन शुरू

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (सीबीएसई) की ओर से सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 11 मई से 10 जून 2026 तक जारी रहेगी। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। सीटीईटी सितंबर 2026 में एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये फीस देनी होगी। एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।



सेवारत टीचरों के लिए सीटीईटी पास करना अनिवार्य, लाखों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार-

टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यूपी, झारखंड, एमपी व राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो बिना टीईटी पास किए वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अब इन टीचरों को 2 साल (सितंबर 2025 - कोर्ट के फैसले की तिथि से) में टीईटी पास करना ही होगा वरना या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस कड़े फैसले से सिर्फ उन्हें छूट मिलेगी जिनकी नौकरी 5 साल की बची है लेकिन इन्हें भी अगर प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना ही पड़ेगा। सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु व यूपी समेत कई राज्य पुनर्विचार याचिका दायर कर चुके हैं हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

सर्राफा कारोबारियों ने जताया विरोध पीएम से फैसलों पर पुनर्विचार की मांग

अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद की बैठक में व्यापार पर असर डालने वाले प्रस्तावों का विरोध, रोजगार बचाने की उठाई मांग

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद की आपातकालीन बैठक में सर्राफा कारोबारियों ने सोने से जुड़े प्रतिबंधों और व्यापारिक गतिविधियों पर असर डालने वाले प्रस्तावों का कड़ा विरोध जताया। परिषद पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से सर्राफा व्यवसायियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णयों पर पुनर्विचार करने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए पुष्पेंद्र जायसवाल ने कहा कि भारत में सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि स्त्री धन माना जाता है। उन्होंने कहा कि बीमारी, बच्चों की शिक्षा, शादी-विवाह और अन्य आपात परिस्थितियों में घरों में रखा सोना परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनता है।

ऐसे में ज्वेलर्स और सुनारों के व्यापार पर रोक लगाना लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर डालेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से चीन से आने वाले सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने, सांसदों और विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करने तथा सरकारी खर्चों को कम करने की मांग की।



परिषद ने सुझाव दिया कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को और प्रभावी बनाकर घरों में पड़े सोने को आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा जाए, जिससे सोने के आयात की आवश्यकता कम हो सके। बैठक में वन नेशन-वन टैक्स व्यवस्था लागू करने और इनकम टैक्स समाप्त करने की भी मांग उठाई गई। पदाधिकारियों ने

सवाल किया कि क्या शादी-विवाह और शुभ कार्य बिना मंगलसूत्र, बिछिया, कड़े और पायल के संभव हैं। बैठक में शीलू वर्मा, पंकज वर्मा, वेद गुप्ता, मनोज वर्मा, दुर्गेश सोनी, सर्वेश वर्मा, संजीव, अजय वर्मा, अमित मिश्रा, राजन वर्मा, कमल वर्मा समेत कई सर्राफा कारोबारी मौजूद रहे।

सम्पादकीय

एमएसपी हकीकत न बनने से मजबूरी में बिक्री

कहने को तो देश डिजिटल क्रांति के दौर में पहुंच चुका है और वित्तीय लेनदेन से लेकर तमाम क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक वरदान साबित हो सकती है। लेकिन हमें यह मानकर चलना चाहिए कि देश का परंपरागत किसान डिजिटल सुविधाओं के उपयोग में खुद को सहज महसूस नहीं करता। आधुनिक डिजिटल तकनीक का प्रयोग नई पीढ़ी की सोच के अनुरूप है, लेकिन पुरानी पीढ़ी इसके उपयोग में खुद को असहज पाती है। कमोबेश किसानों के कल्याण के लिए बनाये गए मंडी पोर्टलों पर भी यही बात लागू होती है। जाहिरा तौर पर किसानों के लिये मंडी पोर्टलों का उपयोग आसान होना चाहिए। बाकायदा किसानों को डिजिटल साक्षर बनाने की मुहिम चलाने की जरूरत भी है। सही मायनों में डिजिटलीकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि उपजों की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना था। लेकिन हरियाणा में जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। दरअसल, हम एक आम किसान से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह शहरी लोगों की तरह पोर्टलों, पासवर्डों और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों के जाल का सहजता से उपयोग कर सके। यही वजह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ उठाने के लिये उसे एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर की मंडियों से द ट्रिब्यून में प्रकाशित हालिया रिपोर्टों से एक जैसा पैटर्न नजर आया है। अब राज्य में फसलों की बिक्री के लिये अनिवार्य पोर्टल- ई-खरीद और मेरी फसल, मेरा ब्योरा यानी एमएफएमबी- साइट क्रैश, डेटा विसंगतियों और सत्यापन की विफलताओं से ग्रस्त है। जिससे कई तरह की समस्याओं से किसानों को रूबरू होना पड़ रहा है। यहां तक कि कई जिलों में, किसानों को गेट पास तक नहीं दिए गए हैं। वजह यह बतायी जा रही है कि किसानों का रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहा है। कई बार अंतिम व महत्वपूर्ण क्षणों में सर्वर ने काम नहीं किया। जिसका खमियाजा फसल बेचने आने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल, ऐसी अनेक तकनीकी जटिलताओं के परिणाम तात्कालिक व गंभीर बताये जाते हैं। किसानों की फसल तो बिक्री के लिये तैयार है, लेकिन कतिपय कारणों से उसे मंडियों में प्रवेश करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है किसान अपने खून-पसीने की फसल निजी व्यापारियों को बेचने को विवश हो जाते हैं।

किसान की मजबूरी ये होती है कि वह जल्द से जल्द फसल बेचना चाहता है। उसे अपने पहले के खर्च निकालने हैं और अगली फसल की तैयारी करनी है। जिसके चलते वह तुरंत भुगतान की आस में कम दाम में भी व्यापारियों को फसल बेचने को बाध्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं कर रही हैं, लेकिन फसल की आवक का एक छोटा हिस्सा ही खरीद पायी हैं। जो फसल खरीद के वायदे और वास्तविक तैयारी के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। कुछ आंकड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। विशेष रूप से, हरियाणा में गेहूँ की खरीद को 80 लाख टन से घटाकर 72 लाख टन करने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते उन्हें आर्थिक घाटा उठाना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि जो अनाज एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है, उसे किसान व्यापारियों को एमएसपी से 400 से पांच सौ रुपये कम दाम पर बेचने को मजबूर है। यानी एमएसपी के मूल उद्देश्य के विपरीत यह किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि डिजिटलीकरण का लक्ष्य व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। लेकिन इस प्रणाली की उपयोगिता तभी है जब सर्वर ठीक से काम कर रहा हो। साथ ही लोग इसका उपयोग बेहतर ढंग से करना जानते हों। यह प्रक्रिया छोटे और गरीब व निरक्षर किसानों को प्रोसेस से बाहर कर देती है। जिनकी सेवा का दावा व्यवस्था अक्सर करती है। एक विसंगति यह भी कि इसमें कोई बैकअप सिस्टम नहीं है। पोर्टल के फेल होने पर खरीद रुक जाती है। यदि एमएसपी का लाभ कमजोर डिजिटल प्रणाली की वजह से किसान को नहीं मिलता, तो यह किसानों का सुरक्षा कवच नहीं रह जाता है। बाकायदा किसानों को डिजिटल साक्षर बनाने की मुहिम चलाने की जरूरत भी है। सही मायनों में डिजिटलीकरण का मुख्य उद्देश्य कृषि उपजों की खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाना था। लेकिन हरियाणा में जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। दरअसल, हम एक आम किसान से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह शहरी लोगों की तरह पोर्टलों, पासवर्डों और प्रक्रियात्मक पेचीदगियों के जाल का सहजता से उपयोग कर सके। यही वजह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ उठाने के लिये उसे एक जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ा है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस: कृषि और डेयरी क्षेत्र में तकनीकी क्रांति का नया दौर

प्रो. दिनेश चन्द्र राय, कुलापति, बीआर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार

हर साल 11 मई का दिन भारत के इतिहास में गर्व और शौर्य की याद लेकर आता है। आज से करीब तीन दशक पहले पोखरण की तपती धरती पर भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन आज, जब हम साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब तकनीक का अर्थ और भी व्यापक हो गया है। अब तकनीक सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे खेतों की मिट्टी और गांवों की डेयरी को समृद्ध बनाने की सबसे बड़ी चाबी है। भारत का सफर एक आयात-निर्मात राष्ट्र से वैश्विक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने तक का रहा है।



लेखक के बारे में- प्रो. दिनेश चन्द्र राय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और वर्तमान में बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलापति हैं। तीन दशकों से उनका शोध कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रहा है।

जो तकनीकी बदलाव आ रहे हैं, वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। अब हम पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ ड्रोन से खेतों की निगरानी और मिट्टी की सेहत की डिजिटल जांच अब भविष्य की बात नहीं, बल्कि हकीकत बनती जा रही है। डेयरी क्षेत्र में यह बदलाव एक बड़ी क्रांति के रूप में उभर रहा है। दूध के उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण तक, तकनीक ने गुणवत्ता और कमाई दोनों को बढ़ाया है। आज हम ऐसे फंक्शनल फूड और डेयरी उत्पाद तैयार कर रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं। जब हम दूध में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्वों को तकनीक के जरिए सुरक्षित रखते हैं, तो उसकी मांग वैश्विक बाजार में बढ़ जाती है। इसी तरह, बाजार (श्री अन्न) जैसे हमारे पारंपरिक मोटे अनाजों को जब आधुनिक फूड इंजीनियरिंग से जोड़ा जाता है, तो वे दुनिया के लिए सुपरफूड बन जाते हैं। यह तकनीकी विकास हमारे किसानों को महज एक अन्नदाता से बदलकर एक कृषि-उद्यमी बना देगा, जिससे गांवों से पलायन रुकेगा और खेती एक मुनाफे वाला पेशा बनेगी।

शिक्षा और नवाचार का लोकतंत्रीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे छात्रों के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे प्रयोगों और नए आविष्कारों से जोड़ा जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालयों का लक्ष्य अब केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो नई मशीनें बनाएं और नए स्टार्टअप शुरू करें।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यह याद करने का दिन है कि आत्मनिर्भरता की कुंजी विज्ञान और तकनीक के सही इस्तेमाल में छिपी है। विकसित भारत का रास्ता हमारे लैब और खेतों से होकर गुजरता है। साथ ही ये संकल्पित होने का दिवस भी है कि हम विज्ञान का इस्तेमाल देश की गरीबी दूर करने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की सिद्धि के लिए करेंगे।

आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है। चाहे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराना हो या फिर देश के छोटे से छोटे दुकानदार के पास डिजिटल भुगतान की सुविधा पहुँचाना, भारत ने साबित कर दिया है कि हमारे पास दुनिया का सबसे शानदार तकनीकी दिमाग है। आज भारत की पहचान एक ऐसी महाशक्ति के रूप में है जो मुश्किल से मुश्किल काम को कम लागत और स्वदेशी तकनीक के जरिए बेहतर तरीके से करना जानती है।

खेती और डेयरी: ग्रामीण समृद्धि का मूल मंत्र

एक खाद्य वैज्ञानिक के तौर पर मेरा मानना है कि भारत की असली तरक्की तभी होगी जब हमारे गांव और किसान आधुनिक विज्ञान से जुड़ेंगे। आज खेती और डेयरी क्षेत्र में

भाजपा को परखने के औजार बदलने चाहिए

राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अनेक विचारक स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण पश्चिमी राष्ट्रवाद से सर्वदा विपरीत है। पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर यूरोपीय राजनीतिक अनुभवों के चश्मे से देखने की कोशिश करता है। वहां राष्ट्रवाद का अर्थ सत्ता विस्तार व नस्लीय वर्चस्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल जीत ने केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों का भी ध्यान आकर्षित किया है।

सभी अपने-अपने मापदण्डों पर इस चुनाव परिणाम को परख रहे हैं परन्तु पुराने ढर्रे पर चलते हुए फिर से गलती पर गलती दोहराते लगते हैं। यहां के विपक्ष की मानें तो यह एसआईआर के प्रयोग से निकला विजयमार्ग है तो विदेशी विश्लेषक फिर से जिंगल बैल जिंदल बैल की तरज पर साम्प्रदायिकता का गीत गाने लगे हैं। इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम बताते हैं कि भाजपा ने कहीं पहली बार पांव जमाए हैं, कहीं वह फिर

से सत्ता में आई है तो कहीं उसने अपना जनाधार बढ़ाया है। अगर केरल जैसे राज्य में वामपंथी दलों को भाजपा के प्रभाव के डर से अयप्पा के दर्शन करने पड़ें, भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से बंजर कहे जाने वाले बंगाल में कमल की फसल लहलहाने लगे, द्रविड़ राजनीति के केंद्र तमिलनाडू में उसकी आहट सुनने लगे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विरोधी इस दल को गलत औजारों से परख रहे हैं। विरोधी भूलते हैं कि देश का मतदाता मदिहीन नहीं है, वह सुशासन व विकास को अपनी पसंद बनाता जा रहा है। अगर कोई दल संविधान के अनुरूप काम करते हुए जनता की पसंद बन रहा है तो विरोधियों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। भाजपा केंद्र और बहुत से राज्यों में वर्षों से शासन में है। अंधविरोध के चरम पर जा कर भी शासन व संवैधानिक व्यवस्था के किसी मान्य मापदण्ड पर विपक्ष अभी तक ऐसा कोई मुद्दा तराश नहीं पाया है जो जनता को भी मान्य हो।



यहां तक कि प्रधानमंत्री कई बार चुटकी ले चुके हैं कि सार्वजनिक जीवन में विपक्ष उनकी कोई तथ्यात्मक आलोचना करने में असफल रहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता तक पहुंचते ही वैश्विक वैचारिक गलियारों में भी बेचैनी पैदा हो गई है। विदेशी मीडिया के बड़े हिस्से ने भारत में लोकतंत्र, अल्पसंख्यक अधिकार और चुनावी निष्पक्षता पर अचानक सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन और अल जजीरा जैसे मंचों पर फिर से यह विमर्श तेजी से गढ़ा जाने लगा कि भारत हिन्दू राष्ट्रवाद की ऐसी दिशा में बढ़ रहा है, जहां लोकतंत्र व बहुलता खतरे में है। विदेशी मीडिया में

ज्यादा चर्चा बंगाल की है। सवाल यही है कि क्या चिंता वास्तव में लोकतंत्र की है या उस सियासी बदलाव की, जिसने दशकों पुराने वामपंथ और छद्मधर्मनिरपेक्षता के वैचारिक गढ़ को ध्वस्त कर दिया? जब भाजपा हारती है, तो विदेशी मीडिया भारत की लोकतांत्रिक परिपक्वता की तारीफ करता है, पर जैसे ही वह निर्णायक जनादेश लेकर आती है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया संदेह और संस्थागत संकट की भाषा में बदल जाती है। श्रेष्ठभावना से ग्रसित पश्चिमी जगत कहीं यह तो नहीं मानता कि भारतीय मतदाताओं में राजनीतिक समझ का अभाव है राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अनेक विचारक स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण पश्चिमी राष्ट्रवाद से सर्वदा विपरीत है। पश्चिमी मीडिया भारत को अक्सर यूरोपीय राजनीतिक अनुभवों के चश्मे से देखने की कोशिश करता है। वहां राष्ट्रवाद का अर्थ सत्ता विस्तार व नस्लीय वर्चस्व रहा है। जबकि भारत में

राष्ट्रवाद सांस्कृतिक, सभ्यतागत पहचान और ऐतिहासिक आत्मबोध से जुड़ा है। इसे विदेशी मीडिया समझ नहीं पाता। इसीलिए वो हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण को सीधे अल्पसंख्यक-बहुसंख्यकवाद से जोड़ देता है। यही कारण है कि बंगाल में भाजपा की जीत को पश्चिम के विश्लेषकों ने लोकतांत्रिक परिवर्तन के बजाय हिंदू राष्ट्रवादी कब्जे की तरह प्रस्तुत किया गया। एसआईआर पर अर्धसत्य दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिणामों के बाद वोट चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग बताया। विदेशी मीडिया ने इन आरोपों को लगभग बिना तथ्य जांचे ही अपने विमर्श का आधार बना लिया। विशेष रूप से एसआईआर को मुस्लिम मतदाताओं को हटाने की साजिश के रूप में पेश किया गया, जबकि हटाए गए 91 लाख नामों में 63 प्रतिशत हिंदू मतदाता थे। बड़ी संख्या में नाम मृत, डुप्लिकेट, स्थायी रूप से स्थानांतरित या फर्जी पाए गए थे।

मौत बनकर दौड़ी बस, ओवरटेक के दौरान एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा

डबल डेकर बस ट्रक से टकराई दो यात्रियों की मौत, 11 घायल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। अरौल क्षेत्र में सोमवार तड़के लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। अरौल टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार डबल डेकर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बिहार के दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक पलट गया और बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डबल डेकर बस संख्या बीआर 28 पी 4659 दूसरी बस को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान आगे चल रहा ट्रक संख्या नंबर आरजे 11 जीबी 5871 अचानक धीमा हो गया। तेज रफ्तार होने के कारण बस चालक नियंत्रण नहीं रख सका और बस सीधे ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद एक्सप्रेस वे पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और यूपीडी की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। टेग्रा एक्सप्रेस की यह बस पटना से तकरीबन 40 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे एक्सप्रेस वे के किलोमीटर-221 पर अरौल क्षेत्र में हुआ। जिस ट्रक से बस टकराई उसमें आरारोट



लदा था और वह सिलीगुड़ी से सहारनपुर जा रहा था।

बिल्हौर एसीपी सुभाष चंद्र और अरौल इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को कानपुर रेफर किया गया। रास्ते में बबलू पुत्र उमेश (25) और नीरज पुत्र दर्शन पटेल निवासी सहनवा, थाना मधुवन, जिला मोतिहारी बिहार की मौत हो गई।

घायलों में रितेश पुत्र रामबालक निवासी सहनवा, मोतिहारी बिहार,



विकलेश पुत्र गिरीश चंद्र निवासी एटा, ट्रक चालक, सुदीप सिंह निवासी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, वीरपाल पुत्र हाकिम

सिंह निवासी ग्वालियर, बस का सेकेंड ड्राइवर, रजत कुमार निवासी औरैया, बस हेलपर, बिट्टू पाल निवासी दिल्ली, निरंजन

→ टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक पलट गया और बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया

हैलट अस्पताल में मटकते रहे घायल

घायल रजत कुमार और विकलेश ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें एंबुलेंस से कानपुर लाया गया, लेकिन हैलट अस्पताल पहुंचने पर काफी देर तक इलाज के लिए इधर-उधर मटकना पड़ा। उनका आरोप है कि समय पर डॉक्टर नहीं मिलने से घायल यात्री परेशान रहे। कई लोग दर्द से कराहते रहे, जबकि परिजन स्ट्रेचर और उपचार की व्यवस्था के लिए दौड़ते नजर आए। बाद में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया।

निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, प्रीति निवासी रुद्रपुर बिहार और आसिफ निवासी झज्जर हरियाणा समेत अन्य यात्री शामिल हैं। हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और पलटे ट्रक को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

छह माह की गर्भवती नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुहपोछा गांव में रविवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर प्रताड़ना और लापरवाही के आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, मुहपोछा गांव निवासी संजय गौतम की पत्नी 19 वर्षीय सुनीता उर्फ मनीषा की शादी 4 जून 2025 को हुई थी। परिजनों के अनुसार मनीषा करीब छह माह की गर्भवती थी। शनिवार देर रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और रक्तस्राव होने लगा। आनन-फानन

में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतका के पिता का आरोप है कि शादी के बाद से बेटी को लगातार परेशान किया जाता था। उन्होंने दामाद पर आए दिन विवाद और मारपीट करने के आरोप लगाए। पिता का कहना है कि 26 अप्रैल को एक शादी समारोह में भी मनीषा के साथ मारपीट की गई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेटी की मौत की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई।

ग्रामीणों के मुताबिक, मौत के बाद ससुराल पक्ष अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गया था। इसी दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।



पेशी से बच रहा पाँक्सो आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। शिवराजपुर थाना पुलिस ने पाँक्सो एक्ट और छेड़छाड़ के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी लगातार अदालत में पेशी से बच रहा था, जिसके चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

पुलिस के मुताबिक दोड़ेपुर चिरंजीपुरवा गांव निवासी छोटा उर्फ छुट्टन पुत्र परशुराम के खिलाफ वर्ष 2018 में



छेड़छाड़ और पाँक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला न्यायालय

→ कई तारीखों से कोर्ट में नहीं हो रहा था हाजिर

में विचाराधीन है, लेकिन आरोपी कई तारीखों से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। थानाध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शनिवार को दबिश देकर आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में उपनिरीक्षक शिवम कुमार और उपनिरीक्षक अटल कुमार भी शामिल रहे।

स्वच्छ गांव बनाने को नानामऊ में जागरूकता अभियान

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो, बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर विकासखंड की ग्राम पंचायत नानामऊ में संभव फाउंडेशन की ओर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत स्वच्छता जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सीआरपी हरिओम द्विवेदी ने गांव के विभिन्न मोहल्लों में घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ग्रामीणों को बताया गया कि सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। लोगों से अपील की गई कि वे घरों का कचरा केवल कूड़ा संग्रहण वाहन में ही डालें, जो प्रतिदिन गांव में डोर-टू-डोर पहुंचकर कचरा एकत्र कर रहा है। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने भी स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग का भरपूर इलाका दिया। संस्था की ओर से कहा गया कि गांव को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

दरियानेवादा टोल पर चला सघन चेकिंग अभियान, 300 वाहनों की जांच

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर दरियानेवादा टोल प्लाजा के पास ट्रैफिक पुलिस और शिवराजपुर पुलिस ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 300 वाहनों की सघन जांच की गई।

डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी ट्रैफिक,

→ ड्रिंक एंड ड्राइव में 21 चालान, हटर और प्रेशर हॉन वाले भी कार्रवाई की जद में

एसीपी बिल्हौर और थाना प्रभारी शिवराजपुर की मौजूदगी में हुई कार्रवाई में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 21 लोगों के खिलाफ ड्रिंक एंड ड्राइव के

तहत चालान किया गया। वहीं हटर और प्रेशर हॉन का इस्तेमाल कर नियमों का उल्लंघन करने वाले चार वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि सड़क पर लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि



नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

आफशां की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी, मुख्तार गैंग में मचा हड़कंप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मऊ-गाजीपुर पुलिस की सात टीमों ने कई ठिकानों पर दी दबिश, करीबी लोगों से घंटों पूछताछ

मऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी और एक लाख रुपये की इनामी आफशां अंसारी की तलाश में मऊ और गाजीपुर पुलिस ने रविवार को बड़ा अभियान चलाया। दोनों जिलों की संयुक्त सात टीमों ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर मुख्तार गैंग से जुड़े लोगों से पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच तेज कर दी गई है।

सुबह करीब नौ बजे पुलिस टीम मऊ के मिर्जाहादीपुरा इलाके में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तैय्यब पालकी के आवास पहुंची, जहां लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस ने कोपागंज थाना क्षेत्र के लीलारी भरारी निवासी अरविंद कुमार सिंह और सरायलखंसी क्षेत्र के उमेश सिंह के घर भी दबिश देकर जानकारी जुटाई। हालांकि इन स्थानों से कोई ठोस सुराग मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। उधर गाजीपुर में पुलिस ने मोहम्मदाबाद

के मंगल बाजार निवासी और मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार मंसूर अहमद अंसारी तथा गौस मुइनुद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी से पूछताछ की। सैदपुर के सिकंदरा गांव में लालजी यादव से भी कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी के दौरान मिले इनपुट्स के आधार पर आफशां अंसारी के संभावित ठिकानों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

एसपी मऊ कमलेश बहादुर ने बताया कि आफशां अंसारी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं गाजीपुर एसपी डॉ. ईराज राजा ने कहा कि जांच में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार आफशां अंसारी के खिलाफ मऊ में गैंगस्टर समेत चार और गाजीपुर में दस मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार हो रही कार्रवाई से मुख्तार गैंग से जुड़े लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। कई संदिग्ध भूमिगत हो गए हैं, जबकि कुछ ने अपने ठिकाने बदल लिए हैं। पुलिस टीमों लगातार संभावित स्थानों पर नजर बनाए हुए हैं।



नोएडा से कुशीनगर तक फैला आतंकी नेटवर्क जांच में जुटी एटीएस

इंस्टाग्राम पर युवकों को जोड़कर दिए जा रहे थे टारगेट किलिंग के टास्क

नोएडा से पकड़े गए सदिग्धों के तार दुबई और पाकिस्तान तक जुड़े



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए सदिग्ध आतंकीयों का

नेटवर्क तैयार किए जाने का बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की जांच में सामने आया है कि इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर दो से चार युवकों के छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर उन्हें पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अफसरों और

स्थानीय नेताओं पर हमले करने के निर्देश दिए जा रहे थे।

जांच एजेंसियों के मुताबिक इन युवकों को संवेदनशील स्थानों की फोटो और वीडियो भेजने के साथ-साथ टारगेट किलिंग जैसे खतरनाक टास्क भी सौंपे गए थे। एटीएस अब बाराबंकी निवासी दानियाल अशरफ और कुशीनगर निवासी कृष्णा मिश्रा से दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रही है। दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए सोमवार को अदालत में अर्जी दाखिल की जाएगी। एटीएस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि दानियाल और कृष्णा के अलावा पहले गिरफ्तार किए गए तुषार और समीर अलग-अलग मॉड्यूल में काम कर रहे थे। एजेंसियों को अब तक इन चारों के बीच सीधा संपर्क नहीं मिला है, जिससे अंदेशा है कि ऐसे कई छोटे आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं, जिन्हें अलग-अलग पाकिस्तानी हैंडलर ऑपरेट कर रहे हैं।

इससे पहले यूपी एटीएस ने नोएडा से मेरठ निवासी तुषार और दिल्ली निवासी समीर को गिरफ्तार किया था।

दोनों पर आईएसआई और शहजाद भट्टी के लिए काम करने का आरोप है। जांच में पता चला कि उन्हें एक्स-मुस्लिम लोगों की हत्या, टारगेट किलिंग और नए युवकों को आतंकी नेटवर्क से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। एजेंसियों के अनुसार, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों को दुबई भेजने की योजना भी तैयार थी। अब एटीएस मोबाइल फोन से मिले संदिग्ध नंबरों के जरिए इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

सुवेंदु अधिकारी के करीबी की हत्या में बलिया का शूटर अयोध्या से गिरफ्तार

» टोल पर यूपीआई से पेमेंट ने उधेड़ी हत्याकांड की परतें

समीर शाही/स्वराज इंडिया

अयोध्या। राजनीति की बिसात पर बिछी एक और खूनी चाल आखिरकार अयोध्या तक आ पहुंची। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में बंगाल पुलिस ने बलिया के कथित शूटर राज सिंह को अयोध्या से दबोच लिया। उसके दो साथी बिहार के बक्सर से गिरफ्तार किए गए हैं।

गिरफ्तारी के बाद बंगाल पुलिस बिना शोर-शराबे के तीनों को कोलकाता ले गई। बताया जाता है कि यह हत्या कोई आवेश में चला ट्रिगर नहीं, बल्कि मिनट-दर-मिनट लिखी गई साजिश थी। हमलावरों को इस बात तक की जानकारी थी कि चंद्रनाथ रथ वाहन में किस स्थान पर बैठे होंगे। यही वजह है कि पुलिस इसे पेशेवर सुपारी किलरों की करतूत

मान रही है। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि इस पूरे ऑपरेशन में आठ से अधिक लोग शामिल थे और स्थानीय स्तर पर भी मदद पहुंचाई गई।

विडंबना देखिए, जिन अपराधियों ने हत्या की पटकथा इतनी सफाई से लिखी, वही एक यूपीआई पेमेंट पर मात खा गए। टोल प्लाजा पर हुए ऑनलाइन भुगतान ने लोकेशन खोल दी और पुलिस उनके पीछे जा पहुंची। अब बंगाल पुलिस इस हत्याकांड के पीछे बैठे असली चेहरे और संभावित राजनीतिक रिश्तों की परतें खोलने में जुटी है। हाई प्रोफाइल मर्डर और गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी अधिकारी अभी फिलहाल जानकारी देने से परहेज कर रहा है। बताया जा रहा है बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के बलिया और अयोध्या के अलावा बदायूं में पुलिस इस मर्डर को लेकर शूटरो के तार जोड़ती नजर आई है।



गांधी नगर में बच्चों के लिए बनेगा आधुनिक चिल्ड्रन पार्क

शंकर सिंह/स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। राजपुर नगर पंचायत क्षेत्र के गांधी नगर वार्ड में अब बच्चों को खेलने और लोगों को सुकून के पल बिताने के लिए आधुनिक चिल्ड्रन पार्क की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत बनने वाला यह पार्क क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नगर पंचायत द्वारा करीब 2 लाख 77 हजार 296 रुपये की लागत से पार्क निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है।

नगर पंचायत प्रशासन ने पार्क

झूले, ओपन जिम, आकर्षक लाइटिंग और हरियाली से सजेगा पार्क, तीन माह में पूरा होगा निर्माण



इसी जगह पर बनेगा पार्क



निर्माण के लिए लगभग दो बीघा भूमि का चिन्हांकन कर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा और तीन माह के भीतर पार्क को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के मनोरंजन और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक झूले, स्लाइड, सी-सॉ, ओपन जिम और अन्य खेल उपकरण लगाए जाएंगे। वहीं लोगों के बैठने के लिए आकर्षक बेंच, टहलने के लिए फुटपाथ, हरियाली



मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत नगर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्क में झूले, आकर्षक लाइटिंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा कराया जाएगा।
अधिकांसी अधिकारी नीति त्रिपाठी
राजपुर कानपुर देहात

और सुंदर लाइटिंग की भी व्यवस्था होगी। पार्क का वातावरण ऐसा विकसित किया जाएगा जहां बच्चे सुरक्षित माहौल में खेल सकें और बुजुर्ग व महिलाएं भी समय व्यतीत कर सकें।

स्थानीय लोगों में पार्क निर्माण को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि अब तक गांधी नगर में बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्थित स्थान नहीं था, जिसके कारण बच्चे सड़कों या खाली स्थानों पर खेलने को मजबूर थे। पार्क बनने से बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और क्षेत्र में सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह चिल्ड्रन पार्क सिर्फ मनोरंजन का केंद्र नहीं होगा, बल्कि गांधी नगर की नई पहचान बनेगा।

मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात (माती)। गजनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार को तिलौची रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर एक दर्दनाक हादसे में मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची ग्रोथ सेंटर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान संदीप कुमार पुत्र अनिल कुमार, निवासी ग्राम बारां दौलतपुर, कानपुर नगर के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त उसके पास मिले आधार कार्ड के आधार पर की। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ननिहाल आए 12 वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर की टक्कर से गई जान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद क्षेत्र में सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 12 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और यातायात सुचारु कराया।

सनी पुत्र विनोद राजपूत निवासी ग्राम सेउ भुरउ थाना रसूलाबाद अपनी ननिहाल ग्राम गहरा आया हुआ था। सोमवार सुबह करीब 09:30 बजे वह गहरा-काशीपुर मार्ग पर ग्राम गहरा के सामने पहुंचा था, तभी तेज रफ्तार स्वराज ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि सनी की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। वहीं हादसे में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है।

नवीपुर जैनपुर औद्योगिक परिक्षेत्र छावनी में तब्दील, प्रशासनिक सुलह हुई फेल

सचिन सिंह/स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। नवीपुर जैनपुर औद्योगिक परिक्षेत्र सोमवार को दूसरे दिन भी श्रमिक प्रतिरोध की तीव्रता से धरता रहा। अरविंद फुटवियर में वेतन विसंगति, महंगाई भत्ते की अनदेखी और कथित श्रम शोषण के विरोध में हजारों कर्मचारियों का धरना अनवरत जारी रहा, जिससे उत्पादन व्यवस्था पूर्णतः ठप रही। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेते हुए पीएसी के तीन वाहन मौके पर तैनात कर दिए गए, जिससे औद्योगिक परिक्षेत्र छावनी में तब्दील नजर आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अमला भी सक्रिय रहा। मौके पर पहुंचे एसडीएम एवं मजिस्ट्रेट ने श्रमिक प्रतिनिधियों और कंपनी प्रबंधन के बीच गतिरोध समाप्त कराने के उद्देश्य से लंबी वार्ता कर समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया, किंतु घंटों चली वार्ता के बावजूद सहमति का कोई सूत्र स्थापित नहीं हो सका।

सुबह से ही फैक्ट्री गेट पर एकत्र श्रमिक खून-पसीना हमारा, मुनाफा तुम्हारा और श्रमिक उल्पीड़न बंद करो जैसे नारों के साथ अपना आक्रोश व्यक्त करते रहे। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे कठोर श्रम लिया जा रहा है, लेकिन



» एसडीएम-मजिस्ट्रेट की मध्यस्थता बेअसर, अरविंद फुटवियर में दूसरे दिन भी उत्पादन ठप

» वेतन विसंगति व महंगाई भत्ते पर श्रमिक अडिग, फैक्ट्री गेट पर हजारों कर्मचारियों का प्रतिरोध



प्रतिफलस्वरूप थर्ड ग्रेड के अंतर्गत मात्र 422 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया जा रहा है, जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में परिवार के निर्वहन हेतु अपर्याप्त है।

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि शासन द्वारा घोषित महंगाई भत्ता और संशोधित वेतनमान को जानबूझकर लागू नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि जब नोएडा और गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 21 प्रतिशत वेतनवृद्धि लागू की जा चुकी है, तो जैनपुर के श्रमिकों को इस वैधानिक अधिकार से वंचित रखना सरासर भेदभाव है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अकबरपुर कोतवाली पुलिस के साथ पीएसी की तीन गाड़ियां पूरे क्षेत्र में लगातार निगरानी करती रहीं। सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेन्द्र सिंह भोले के हस्तक्षेप की संभावना भी प्रबल हो गई है। फिलहाल जैनपुर औद्योगिक परिक्षेत्र में उपजा यह असंतोष अब एक फैक्ट्री विवाद से आगे बढ़कर जिले में श्रमिक अधिकारों की निर्णायक लड़ाई का संकेत दे रहा है। प्रशासनिक प्रयास विफल रहने के बाद अब सबकी निगाहें कंपनी प्रबंधन की अगली रणनीति पर टिकी हैं।



अंतर्वेद जंगल में दिखे गिद्धों के झुंड से जगी उम्मीद, पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह



❖ यदि वन क्षेत्र और प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहे तो गिद्धों की संख्या फिर बढ़ सकती



शरद मिश्रा/ स्वराज इंडिया

लखीमपुर खीरी। प्रकृति के सफाईकर्मी कहे जाने वाले गिद्धों की घटती संख्या के बीच रविवार को निघासन क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई। तहसील निघासन के अंतर्वेद जंगल के पास औघड़ बाबा

स्थान के सामने अचानक दर्जनों गिद्ध दिखाई देने से पक्षी प्रेमियों और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। लंबे समय बाद एक साथ इतनी संख्या में गिद्धों का दिखना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।



एक समय था जब ग्रामीण इलाकों में गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे। किसी भी मृत पशु को कुछ ही घंटों में साफ कर देने वाले ये पक्षी पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों में इनकी संख्या तेजी से घटी और अब स्थिति यह हो गई कि गिद्धों का दिखना दुर्लभ माना जाने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार पशुओं में इस्तेमाल

होने वाली कुछ दवाइयों का असर गिद्धों के लिए घातक साबित हुआ, जिससे उनकी संख्या लगातार कम होती चली गई। गिद्धों की कमी का असर पर्यावरण पर भी पड़ा, क्योंकि मृत पशुओं के खुले में पड़े रहने से संक्रमण और गंदगी बढ़ने लगी। रविवार को अंतर्वेद जंगल क्षेत्र में जब ग्रामीणों ने पेड़ों और खुले आसमान में गिद्धों के झुंड को मंडराते देखा तो लोगों ने इसे कैमरों में कैद कर लिया।

क्षेत्र के प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि यदि वन क्षेत्र और प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहे तो गिद्धों की संख्या फिर बढ़ सकती है। वन विभाग से इस क्षेत्र में विशेष संरक्षण अभियान चलाने की मांग की है, ताकि विलुप्ति की कगार पर पहुंचे इन दुर्लभ पक्षियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। गिद्धों की वापसी को पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए बेहद सुखद संकेत माना जा रहा है।

आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में गोला तहसील ने रचा नया कीर्तिमान

प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर बढ़ाया जिले का मान, प्रशासनिक कार्यशैली की हो रही सराहना



प्रतीक्षा त्रिपाठी, एसडीएम गोला

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को लेकर गोला तहसील ने प्रदेशभर में अपनी अलग पहचान कायम की है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में गोला तहसील ने प्रदेश स्तर पर पहला स्थान

प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ताजा जारी रैंकिंग में तहसील को शत-प्रतिशत अंक मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। इस सफलता के पीछे तहसील प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग, पारदर्शी कार्यप्रणाली और शिकायतों के प्रति गंभीरता को प्रमुख कारण माना जा रहा है। एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने लंबित मामलों के त्वरित समाधान के साथ शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि पर भी विशेष ध्यान दिया, जिसके चलते गोला तहसील प्रदेश की शीर्ष रैंकिंग तक पहुंच सकी। गौरतलब है कि गोला तहसील पूर्व में भी आईजीआरएस एवं जनशिकायत निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रही है। लगातार बेहतर कार्यशैली और जवाबदेही के चलते तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली आमजन के बीच विश्वास का केंद्र बनती जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस उपलब्धि पर तहसील प्रशासन को बधाई देते हुए इसे जनहित में सकारात्मक पहल बताया है।

महिला आरक्षण बिल के समर्थन में भाजपाई महिलाओं का प्रदर्शन

सांसद का आवास घेर कर की जोरदार नारेबाजी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखीमपुर खीरी। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों एवं महिला जनप्रतिनिधियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा के आवास का घेराव किया। इस दौरान महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर अपना समर्थन जताया।

भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर बाजार क्षेत्र में मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान नारी शक्ति का सम्मान करो, हम लोगों ने ठाना है, नारी की जिम्मेदारी निभाना है और जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। महिलाओं ने कहा



कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

महिला आरक्षण बिल महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कार्यक्रम में नगर

पालिका अध्यक्ष डॉ. ईरा श्रीवास्तव, लखीमपुर ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, बेहजम ब्लॉक प्रमुख बीना राज, भाजपा जिला मंत्री संगीता पुरी, अनु श्री, अनिता निगम, मंजुलता श्रीवास्तव, उमा राज सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

LAB GROWN DIAMONDS

Everyone Is Wearing Them



ARYAMA®
jewels

Lab Diamonds | Gold Jewellery

7860070809

Merchant Chambers Road, Civil Lines Kanpur

रामनगरी में जमीन का खेल!

फर्जी एग्रीमेंट से करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप

सीजेएम कोर्ट के आदेश से दर्ज हुई एफआईआर, नया घाट से बेलवा खुर्द तक मचा हड़कंप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। प्रभु श्रीराम की नगरी अब जमीन के कथित फर्जीवाड़े को लेकर सुर्खियों में है। करोड़ों की जमीन पर कब्जे के लिए फर्जी कागजात और फर्जी एग्रीमेंट का ऐसा खेल सामने आया है, जिसने प्रशासनिक गलियारों से लेकर साधु-संतों के बीच तक हलचल मचा दी है। मामला इतना गंभीर निकला कि सीजेएम कोर्ट को सीधे दरखल देना पड़ा और कोतवाली नगर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देना पड़ा। मामले में उमाशंकर दास, गौरीशंकर दास, शिवम गुप्ता उर्फ राधे भोजनालय और कुंदन अवस्थी समेत कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन का खेल रचा गया। रामनगरी में चर्चा इस बात की है कि क्या यह सिर्फ चार लोगों का खेल है या फिर जमीन माफियाओं का कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। नया घाट स्थित राधे भोजनालय का नाम सामने आने के बाद शहर में कानाफूसी तेज हो गई है। अदालत में अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह की पैरवी के बाद कोर्ट ने साफ संकेत दे दिए कि मामला मामूली नहीं है। अब पुलिस दस्तावेजों की परतें खोल रही है और शहर पूछ रहा है आखिर इस जमीन खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है?

शहीद के सम्मान पर कीचड़ की राजनीति

जिस घर तक तिरंगा पहुंचा, वहां आज तक सड़क नहीं पहुंची

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या की राजनीति में वादों का मौसम हर चुनाव में खूब बरसता है, लेकिन मझवां की बदहाल सड़क आज फिर यह सवाल पूछ रही है कि क्या इस देश में शहीदों का सम्मान सिर्फ मंचों की भाषणबाजी तक सीमित रह गया है?

जिस घर का बेटा तिरंगे में लिपटकर लौटा, उस घर तक पहुंचने के लिए आज भी लोग कीचड़, गड्डों और अपमान से होकर गुजरने को मजबूर हैं। यह सिर्फ सड़क नहीं, व्यवस्था के संवेदनहीन चेहरे की दरकती तस्वीर है।

मझवां की गलियों में रहने वाले लोग वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं। नेताओं ने दौरे किए, कैमरों के सामने आश्वासन दिए, शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के नाम पर चौराहे का नामकरण करने की घोषणा भी हुई, लेकिन अफसोस... न सड़क बनी और न सम्मान का वह पत्थर लगा, जिस पर शहीद का नाम लिखा जाना था। चुनावी पोस्टरों में राष्ट्रवाद चमकता रहा और शहीद का परिवार धूल फांकता रहा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सेना के अधिकारियों को भी शहीद के घर पहुंचने के लिए आरटीओ कार्यालय के पीछे से अस्थायी रास्ता बनाना



पड़ा, तब सत्ता के जिम्मेदार लोगों की आत्मा क्यों नहीं कांपी? क्या यही 'राष्ट्रभक्ति' है? क्या यही शहीदों के प्रति सम्मान है? मझवां की टूटी सड़क अब सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं रही, यह उन खोखले नारों पर

तमाचा बन चुकी है, जिनमें सैनिकों के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन उनके परिवारों के दर्द पर चुप्पी साध ली जाती है। यहां कीचड़ में सिर्फ रास्ते नहीं धंसे हैं, नेताओं के वादे और संवेदनाएं भी दफन पड़ी हैं।

सरयू की धार से दशरथ समाधि पर खतरा, अब जागा सिस्टम



कटान रोकने को करोड़ों की कवायद, बरसात से पहले बचाव कार्य पूरा करने की दौड़

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में सरयू की तेज धार

अब भगवान श्रीराम के पिता महाराज दशरथ की समाधि पर खतरा बनकर मंडरा रही है। बरसात में होने वाली कटान से समाधि स्थल को बचाने के लिए बाढ़ कार्य खंड ने करोड़ों रुपये की सुरक्षा योजनाओं पर काम तेज कर दिया है।

बिल्वहरिघाट तटबंध के अंतिम छोर पर स्थित दशरथ समाधि को सुरक्षित रखने के

लिए बोल्टर पिचिंग और पुराने स्परों की मरम्मत युद्धस्तर पर चल रही है।

अधिशाली अभियंता संजय सिंह के मुताबिक लगभग 13 करोड़ रुपये की योजनाओं के तहत सुरक्षा कार्य शुरू कर दिया गया है।

विभाग को डर है कि यदि बरसात से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो उफनती सरयू निर्माण कार्य में बड़ी बाधा बन सकती है। यही वजह है कि अधिकारियों को हर हाल में 30 जून तक काम पूरा कराने का निर्देश दिया गया है।

इधर दशरथ समाधि तक पहुंचने वाला फोरलेन मार्ग भी अंतिम चरण में है। राम मंदिर सर्किट से जुड़ने के बाद यह इलाका धार्मिक ही नहीं, बल्कि वीआईपी और कारोबारी गतिविधियों का नया केंद्र बनता जा रहा है। पास में सोलर प्लांट, फाइव स्टार होटल और आवासीय परियोजनाएं आकार ले रही हैं। अब सवाल यही है क्या सरयू की धार के सामने करोड़ों की यह सुरक्षा दीवार टिक पाएगी या हर साल की तरह फिर खतरे की घंटी बजेगी?

रामलला का दरबार तैयार, अब विदा होंगी निर्माण कंपनियां

30 जून तक हट जाएंगी एलएंडटी और टीसीएस की टीमें

मंदिर परिसर में अब हाईटेक सुरक्षा और 7डी संग्रहालय की तैयारी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में वर्षों से गुंज रही मशीनों की आवाज अब थमने वाली है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ऐलान किया है कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य पूरा हो चुका है

और 30 जून तक निर्माण कंपनियां लार्सन एंड टुब्रो तथा टीसीएस मंदिर परिसर से हट जाएंगी।

हालांकि, मंदिर की निगरानी और रखरखाव के लिए एलएंडटी की एक स्थायी टीम रामलला के दरबार में तैनात रहेगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि सभी उप मंदिरों में दर्शन-पूजन सुचारू रूप से चल रहा है और अब फोकस सुरक्षा व भव्यता बढ़ाने पर है। राम मंदिर परिसर के चारों ओर चार किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिसे 2026 के अंत तक पूरा



करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ट्रस्ट कार्यालय और अत्याधुनिक संग्रहालय का निर्माण तेजी से जारी है। संग्रहालय में 20 गैलरियां होंगी। जिनमें एक खास '7D गैलरी' भक्तों को ऐसा अनुभव देगी मानो वे सीधे रामलला के समक्ष खड़े हों। अब रामनगरी सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि तकनीक और भव्यता का नया प्रतीक बनने की ओर बढ़ रही है।

महिला आरक्षण पर घिरी सियासत, फूटा महिलाओं का गुस्सा

सांसद आवास के बाहर गरजे नारे, गेट बंद होने पर और भड़कीं महिलाएं

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर छिड़ी राजनीतिक लड़ाई अब सड़क पर खुलकर दिखाई देने लगी है। रविवार को सहायक गंग स्थित सांसद अवधेश प्रसाद के आवास पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा।

सैकड़ों महिलाओं ने आवास का घेराव कर 'महिला विरोधी सोच नहीं चलेगी, 33 प्रतिशत आरक्षण हमारा अधिकार' और अवधेश प्रसाद मुर्दाबाद जैसे नारों से पूरा इलाका गुंजा दिया।

प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप था कि महिला आरक्षण का विरोध कर महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश

की जा रही है। माहौल उस समय और गर्म हो गया जब महिलाओं ने आरोप लगाया कि सांसद ने आवास का गेट अंदर से बंद करा लिया और बाहर निकलकर प्रदर्शनकारियों का सामना तक नहीं किया। इस पर महिलाओं ने तंज कसते हुए

कहा कि जनता के वोट से संसद पहुंचने वाले नेता अब महिलाओं के सवालों से डरने लगे हैं।

डॉ. अंजू पांडेय ने कहा कि आधी आबादी अब केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि जवाब मांगने वाली ताकत बन चुकी है।

वहीं अखण्ड सिंह डिम्पल ने चेतावनी दी कि महिला सम्मान के मुद्दे पर विरोध करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। स्थिति बिगड़ती देख भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।



हंता वायरस से दहशत: तीन मौतों के बाद स्पेन पहुंचा डच क्रूज शिप

दक्षिण अटलांटिक महासागर में हंता वायरस संक्रमण की आशंका से घिरे डच क्रूज शिप एमवी हॉंडियस को आखिरकार स्पेन में प्रवेश मिल गया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। दक्षिण अटलांटिक महासागर में हंता वायरस संक्रमण की आशंका से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना डच क्रूज शिप 'एमवी हॉंडियस' आखिरकार स्पेन पहुंच गया। जहाज पर मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स में संक्रमण फैलने की आशंका के चलते इसे पहले कैनेरी द्वीप समूह के तट से दूर रोक दिया गया था। डब्ल्यूएचओ और स्पेनिश स्वास्थ्य एजेंसियों के सख्त प्रोटोकॉल के बाद यात्रियों को नियंत्रित तरीके से जहाज से उतारा गया।

इस क्रूज शिप पर यात्रा के दौरान हंता वायरस संक्रमण से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में एक डच दंपती और एक जर्मन महिला शामिल हैं। इन मौतों के बाद जहाज को केप वर्डे के पास विशेष निगरानी में क्वारंटीन किया गया था ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। स्वास्थ्य एजेंसियों ने जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों और कर्मचारियों की जांच की और संदिग्ध



क्या है हंता वायरस?

हंता वायरस एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक संक्रमण है, जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और अन्य कृन्तकों के मल, मूत्र या लार के संपर्क से फैलता है। यह फेफड़ों और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, शरीर दर्द, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी शामिल हैं।

मामलों की अलग निगरानी शुरू की।

मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि जहाज पर तैनात दोनों भारतीय क्रू सदस्य पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्पेनिश नेशनल सेंटर फॉर इमरजेंसी

मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन के अनुसार दोनों भारतीय नागरिकों को एहतियातन आगे की स्वास्थ्य निगरानी और क्वारंटीन प्रक्रिया के लिए नीदरलैंड्स भेजा गया है।

भारतीय दूतावास लगातार स्पेनिश

यात्रा के दौरान तीन लोगों की मौत के बाद जहाज को कई दिनों तक समुद्र में क्वारंटीन रखा गया। हालांकि भारतीय दूतावास ने जहाज पर मौजूद दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित

प्रशासन और जहाज पर मौजूद भारतीय नागरिकों के संपर्क में बना हुआ है। वहीं डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसियां इस दुर्लभ संक्रमण पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि हंता वायरस सामान्य परिस्थितियों में बड़े स्तर पर इंसान से इंसान में नहीं फैलता, इसलिए फिलहाल इसे वैश्विक महामारी जैसा खतरा नहीं माना जा रहा।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और कृन्तकों के संपर्क से फैलता है। जहाज पर संक्रमण के स्रोत की जांच की जा

भारतीय नागरिक सुरक्षित

- जहाज पर दो भारतीय क्रू सदस्य मौजूद
- दोनों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं
- भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में
- आगे निगरानी के लिए नीदरलैंड्स भेजा गया

तयों बड़ी वैश्विक चिंता?

- समुद्री यात्रा में संक्रमण फैलने का खतरा
- कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क
- डब्ल्यूएचओ कर रहा निगरानी
- हालांकि विशेषज्ञों ने महामारी जैसी आशंका से किया इनकार

रही है। स्पेनिश स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को कुछ दिनों तक मेडिकल निगरानी में रखने का फैसला लिया है। इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं में स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर भी बहस तेज हो गई है।

काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में लगी आग



स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया। टर्किश एयरलाइंस का एक विमान जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, तभी उसके टायर में अचानक आग लग गई। विमान के रनवे पर पहुंचते ही एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ और राहत टीम की त्वरित कार्रवाई से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान के उतरते समय टायर से धुआं और चिंगारियां निकलती दिखाई दीं। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीम मौके पर पहुंच गई। विमान को रनवे पर रोकने के तुरंत बाद

इमरजेंसी गेट खोले गए और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक घटना में किसी यात्री या क्रू सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए एयरपोर्ट संचालन प्रभावित रहा, जबकि अन्य उड़ानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान अत्यधिक घर्षण या तकनीकी खराबी के कारण टायर में आग लगी होगी। विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है और एयरलाइन कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल रहा, लेकिन समय रहते बचाव कार्य होने से एक बड़ा हादसा टल गया।

ट्रंप ने दुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव, होर्मुज पर फिर बढ़ा तनाव

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव कम होने के बजाय और अधिक गहराता दिखाई दे रहा है। युद्ध समाप्त कराने के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बीच ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। इससे पश्चिम एशिया में एक बार फिर अस्थिरता बढ़ने की आशंका तेज हो गई है।

ईरान की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में सभी मोर्चों पर युद्धविराम लागू करने, विशेष रूप से लेबनान में संघर्ष रोकने तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। इसके अलावा तेहरान ने अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने और ईरानी तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिना रोक-टोक बेचने की अनुमति देने की शर्त भी रखी। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देने की मांग दोहराई।

हालांकि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट कर दिया कि यह प्रस्ताव अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी ऐसे समझौते के पक्ष में नहीं है, जिसमें उसकी रणनीतिक और सैन्य स्थिति कमजोर हो। अमेरिकी



युद्धविराम, प्रतिबंध हटाने और तेल निर्यात की मांग पर अड़ा तेहरान, अमेरिका ने कहा- शर्त स्वीकार नहीं

प्रशासन का मानना है कि ईरान अपनी क्षेत्रीय ताकत बढ़ाने के लिए वार्ता का इस्तेमाल कर रहा है।

दूसरी ओर ईरानी राष्ट्रपति मसूज पेजस्कियान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय हितों और संप्रभु अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने दोहराया कि ईरानी जनता किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच जारी इस तनावपूर्ण संवाद में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि ईरान की प्रतिक्रिया

अमेरिका तक पहुंचा दी गई है, हालांकि उन्होंने वार्ता की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की।

तनाव का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दिखाई दे रहा है, जहां जहाजरानी प्रभावित होने लगी है। यह समुद्री मार्ग दुनिया की बड़ी तेल और गैस आपूर्ति का प्रमुख रास्ता माना जाता है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका गहरा गई है।

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमलों तथा उसके बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद यह संघर्ष तेज हुआ था। फिलहाल आठ अप्रैल से युद्धविराम लागू है, लेकिन दोनों देशों के कड़े रुख ने हालात को बेहद नाजुक बना दिया है।

